एच. डी. रेवन्ना

बनाम

जी. पुट्टास्वामी और अन्य

21 जनवरी, 1999

[एम. श्रीनिवासन और यू. सी. बनर्जी, न्यायाधिपति ।

चुनाव कानूनः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: धारा 81, 82, 83, 86 और 117

निर्वाचन याचिका - समर्थन में -शपथ पत्र- में दोष - का स्थिरता -पर प्रभाव - ठहरायाः यद्यपि न तो चुनाव याचिका का सत्यापन और न ही सहायक हलफनामा निर्धारित प्रपत्र में है और याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से यह निर्धारित नहीं किया था कि कौन से आरोप उनकी व्यक्तिगत जानकारी में सही थे और कौन से सूचना पर बताए गए हैं, फिर भी चुनाव याचिका तत्काल रूप से खारिज होने के लिए योग्य नहीं है-चुनाव नियम संहिता, 1961, आर. 94-ए और फॉर्म 25-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908,0.6, आर. 16 और 0.7, आर 11।

चुनाव याचिका -शपथ पत्र का सत्यापन-समर्थन में -दोष - स्थिरता का- प्रभाव- ठहराया : चुनाव याचिका या उसके साथ दिए गए हलफनामे के सत्यापन में दोष ठीक करने योग्य है और घातक नहीं है-कर्नाटक उच्च न्यायालय नियम, 1959, ओ. XI, आर. 4।

चुनाव याचिका-भ्रष्ट आचरण-चुनाव में अस्पष्टता की सामग्री- याचिका में चुनाव को अमान्य करने के लिए कार्रवाई का कारण बनने वाले आवश्यक तथ्य शामिल थे और निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण की काफी वकालत की गई थी- ठहराया: उच्च न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया कि भ्रष्ट आचरण में से एक के संबंध में भी तात्विक तथ्य और पूर्ण विवरण नहीं दिए गए हैं, फिर भी चुनाव याचिका को तत्काल रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है यदि अन्य भ्रष्ट आचरण के संबंध में, सामग्री तथ्य और विवरण धारा 83 (1) की आवश्यकता के अनुसार दिए गए हैं —चुनाव याचिका- सामग्री तथ्य" और सामग्री "विवरण" - धारित के बीच अंतर– : "तात्विक तथ्य" पूरी तरह से निर्धारित किए जाने चाहिए और यदि कोई तथ्य निर्धारित नहीं किया गया है तो उससे संबंधित कोई सबूत पेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी— ही चुनाव याचिका के लिए निर्धारित सीमा अवधि की समाप्ति के बाद

याचिका में संशोधन किया जा सकता है —जहां तक "विवरण" की कमी का संबंध है, अदालत को इसे शामिल करने का अवसर देना चाहिए।

चुनाव याचिका -स्थिरता -विरुद्ध प्रारंभिक आपत्ति –ठहराया: प्रारंभिक आपत्ति का निर्णय करने के लिए परीक्षण यह है कि क्या याचिका में किए गए कथन सही साबित होने पर अनुरोध की गई किसी भी राहत को मंजूरी दी जा सकती है यदि हां, तो याचिका बनाए रखने योग्य है।

धारा 97-अभियोग याचिका-वापस लौटाए गए उम्मीदवार द्वारा दाखिल किया जा सकता है–ठहराया : इसका मतलब यह नहीं है कि लौटे उम्मीदवार ने चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप स्वीकार किए।

चुनाव याचिका –पुनर्गणना — औचित्य का आदेश –ठहराया: उस संबंध में सबूत पेश किए जाने के बाद मुकदमे में निर्णय लिया जाना है।

शब्द और वाक्यांशः "तात्विक तथ्य" और "विवरण" का अर्थ।

राज्य के विधान सभा चुनाव में उत्तरदाता नंबर 1 चार मतों से आगे चल रहा था, जब निर्वाचन अधिकारी ने एक के रूप में पुनः गिनती का आदेश दिया जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को निर्वाचित घोषित किया गया। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय में अपीलार्थी का चुनाव

अमान्य घोषित करने और प्रत्यर्थी संख्या 1 को विधिवत निर्वाचित घोषित करने के लिये याचिका दायर की। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने तर्क दिया कि पुनः गिनती का आदेश निर्वाचन आचरण नियम, 1961 के नियम 63 का अनुपालन करे बिना दिया गया था और यह कि अपीलार्थी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (2), 123 (7) (एफ) और 123 (8) के साथ पठित धारा 100 (1) (बी) और 100 (1) (डी) के दायरे में आने वाली भ्रष्ट गतिविधियाँ की थीं। अपीलार्थी ने पुनः दोषारोपण के लिए याचिका दायर की और चुनाव याचिका संक्षिप्त रूप से ख़ारिज करने के लिए आवेदन भी दायर किए। उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसलिए यह अपील की गई है।

अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि चुनाव याचिका में सत्यापन और हलफनामा नियमों के नियम 94-ए या प्रपत्र 25 के अनुरूप नहीं था, कि प्रतिवादी संख्या 1 ने विशेष रूप से यह निर्धारित नहीं किया था कि कौन से आरोप उनकी व्यक्तिगत रूप से ज्ञात थे और कौनसे जानकारी के आधार पर कहे गए थे, कि भ्रष्ट आचरणों के आरोप अस्पष्ट थे और उनमें तात्विक तथ्य या विवरण नहीं थे, और इसलिए, उक्त दोषों ने

पूरी चुनाव याचिका को दूषित कर दिया था और उसी को खारिज करने योग्य बना दिया था।

प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी द्वारा दोषारोपण याचिका से पता चला कि उसने स्वीकार किया था चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों की सच्चाई को और इसलिए, यह उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में अपील दायर करने के लिए अपीलार्थी के लिए खुला नहीं है था।

अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. न तो सत्यापन और न ही शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में है लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 0के प्रावधान बहुत विशिष्ट हैं। अधिनियम की धारा 86 में चुनाव याचिका को रद्द करने का प्रावधान है धारा 81,82 और 117 का अनुपालन न करने के लिए। धारा 81 चुनाव याचिका प्रस्तुत करने से संबंधित है। यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि धारा 81 की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया था। धारा 82 और 117 वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि धारा 86 , धारा 83 का उल्लेख नहीं करती है और धारा 83 का अनुपालन न करने पर धारा 86

के तहत बर्खास्तगी नहीं होती है। इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि धारा 83 का अनुपालन न करने पर याचिका खारिज हो सकती है यदि मामला सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6 नियम 16 या आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आता है। चुनाव याचिका या चुनाव याचिका के साथ शपथ पत्र के सत्यापन में दोष उपचार योग्य है और घातक नहीं है। [205-जी; 207-सी-एफ)

मुरारका राधे श्याम राम कुमार बनाम रूप सिंह राठौर, **[1964] 3 एस. सी. आर. 573 का अनुसरण।**

ए. सापा बनाम सिंगोरा, **[1991] 3 एस. सी. सी. 375, पर निर्भर ।**

सुब्बाराव बनाम सदस्य, चुनाव न्यायाधिकरण, हैदराबाद, **[1964] 6 एससीआर 213** ; के. एम. मणि बनाम पी. जे. एंटनी, **[1979] 2 एस. सी. सी. 221** और टी. एम. जैकब बनाम ओ . पौलोस, **[1998] 2 एस. सी. सी. 31, संदर्भित।**

विरेन्द्र कुमार सक्लेचा बनाम जगजीवन, **[1972] 1 एस. सी. सी. 826**; डॉ. शिप्रा(श्रीमती.) बनाम शांतिलाल खोइवाल, **[1996] 5 एस. सी.**

सी. 181 और एल. आर. शिवरामगौड़ा बनाम टी. एम. चंद्रशेखर, [1998] एससीएएलई 361, लागू न होना ठहराया।

2. उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका में पाया है कि चुनाव को अमान्य करने के लिए कार्रवाई का कारण बनने वाले आवश्यक तथ्य और अपीलकर्ता द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण के तथ्य पर्याप्त रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सही माना कि तथ्य कुछ भी हो चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप सही थे या गलत यह नहीं माना जाएगा कि चुनाव याचिका किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा नहीं करती है। किसी भी भ्रष्ट आचरण का तात्विक विवरण दें। उच्च न्यायालय ने भ्रष्ट आचरणों में से एक के संबंध में भी इसे सही ढंग से जोड़ा है कि कथित तात्विक तथ्य और उनका पूरा विवरण नहीं दिया गया है, फिर भी चुनाव याचिका को तत्काल बाहर नहीं फेंका जा सकता है, अगर अन्य भ्रष्ट प्रथाओं के संबंध में, तात्विक तथ्य और पूरा विवरण अधिनियम की धारा 83 (1) की आवश्यकता के अनुसार दिया गया है। इसलिए इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि भ्रष्ट आचरण के ये आरोप अस्पष्ट हैं और इनमें तात्विक तथ्य नहीं हैं। [209 - एफ; जी-एच; 210-ए-बी]

3.1 . इस न्यायालय ने बार-बार दोनों के बीच अंतर बताया है ' तात्विक तथ्य' और 'विवरण'। जहाँ तक तात्विक तथ्यों' की पुष्टि की गई है, इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि उन्हें चुनाव याचिका में पूरी तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए और यदि कोई तथ्य निर्धारित नहीं किया गया है, तो याचिकाकर्ता को बाद में उससे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और न ही उसे चुनाव याचिका के लिए निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी। जहां तक विवरणों का संबंध है, विवरणों की कमी के कारण याचिका को सीमित नहीं किया जा सकता है और यदि न्यायालय को लगता है कि विवरण आवश्यक हैं, तो याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने और विवरण शामिल करने का एक अवसर दिया जाना चाहिए । [210 - एफ-जी]

श्री बलवान सिंह बनाम श्री लक्ष्मी नारायण, **[1960] 3 एस. सी. आर. 91, का अनुसरण ।**

राज नारायण बनाम श्रीमती. इंदिरा नेहरू गाँधी, **[1972] 3 एस. सी. सी. 850, पर निर्भर।**

धर्मवीर बनाम अमर सिंह, **[1996] 3 एस. सी. सी. 158, लागू न होना ठहराया।**

3.2 . प्रारंभिक आपत्ति के सभी मामलों में परीक्षण यह देखने के लिए है कि यदि याचिका में किए गए कथन सही साबित होते हैं तो याचिकाकर्ता को मांगी गई राहतों में से कोई दी जा सकती हैं। यदि प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो याचिका की स्थिरता को बरकरार रखना होगा। वर्तमान मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि चुनाव याचिका में निहित आरोप याचिकाकर्ता द्वारा सही साबित किए जाते हैं, तो वह प्रार्थना भाग में निर्धारित राहत प्राप्त करने का हकदार होगा। [212 - एफ-जी]

4. कार्यवाही की शुरुआत में दायर की गई दोषारोपण याचिकाएँ केवल इस आधार पर थी कि भले ही चुनाव याचिका में किए गए अभिकथनों को सही माना गया हो, याचिका खारिज होने योग्य थी क्योंकि यह चुनाव कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी। इसका मतलब यह नहीं है कि अपीलार्थी ने याचिका में लगाए गए आरोपों की सच्चाई को स्वीकार किया था। [205 - बी-सी]

5. सवाल यह है कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर का आदेश देना उचित था मामले की परिस्थितियों में पुनर्गणना और क्या इस तरह की पुनर्गणना चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 63 के दायरे में होना चाहिये, पक्षकारों द्वारा उस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद मुकदमे में निर्णय लिया जाएगा। [208 - एफ]

चंदा सिंह बनाम चौधरी शिवराम वर्मा, **[1975] 4 एस. सी. सी. 393** और एस. बलदेव सिंह बनाम तेजा सिंह स्वतंत्र (मृत), **[1975] 4 एस. सी. सी. 406, लागू न होना माना।**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 14211-13/1996

कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 21.3.96 निर्णय और आदेश से जो कि ई. पी. सं. 16 /1995 में पारित किया गया।

के. एन. भट, एस. के. कुलकर्णी अपीलार्थी के लिए सुश्री संगीता कुमार के लिए

जी. एन. शेषगिरी, श्रीमती रजनी के. प्रसाद, सुश्री नीलम शर्मा और एस.श्रीनिवासन उत्तरदाताओं के लिए ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

श्रीनिवासन, न्यायाधिपति

अपीलकर्ता को कर्नाटक राज्य में 133 होलेनारासीपुरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 26.11.94 को हुए चुनाव में 11.12.94 को निर्वाचित घोषित किया गया था। पहले प्रतिवादी ने चुनाव याचिका 1995 की संख्या 16 दायर की निम्नलिखित आधारों पर कर्नाटक उच्च न्यायालय में :

(ए) चुनाव संचालन नियमों के नियम 1961 के नियम 63 का पालन न करना, (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 (1) (डी) (iv) के प्रावधानों को आकर्षित करते हुए (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित)

(बी) धारा 100(1)(बी) और धारा 100(1)(डी)(ii) के साथ पठित अधिनियम की धारा 123(2), 123(7)(एफ) और 123(8) के दायरे में आने वाले अपीलकर्ता की सहमति से अपीलकर्ता और उसके पिता द्वारा भ्रष्ट आचरण का करित करना ।

2. चुनाव याचिका में आरोप मुख्य रूप से यह थे कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा गिनती पूरी होने के बाद, परिणाम की घोषणा किए बिना और उसे निर्धारित प्रपत्र में दर्ज किए बिना, पुनर्गणना के लिए अपीलकर्ता

द्वारा किए गए अनुरोध पर उक्त अधिकारी द्वारा विचार किया गया था जो कि अपीलकर्ता के पिता एच डी देवगौड़ा, जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने ,से अनुचित रूप से प्रभावित था और समय अंतराल पर वे देश के प्रधानमंत्री बने। यह आरोप लगाया गया था कि पहला प्रतिवादी चार मतों से आगे चल रहा था और अपीलार्थी के पिता, जिन्हें तब तक विधानसभा के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया गया था, ने टेलीफोनिक संचार के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी से कहा कि फिर से गिनती का आदेश दिया जाना चाहिए और अपीलार्थी को चुनाव जीतने में मदद की जानी चाहिए। याचिका के अनुसार, पहले प्रतिवादी द्वारा मनमाने ढंग से और सनकी तरीके से उठाई गई आपत्तियों को दरकिनार करते हुए नियम 63 के अनुपालन के बिना फिर से गिनती का आदेश दिया गया था। इस तरह की पुनः गिनती का आदेश निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिया गया था जो अपीलार्थी के पिता से अनुचित रूप से प्रभावित होकर वह कानून के जनादेश की पूरी तरह से अवज्ञा कर रहा था और चुनाव को दूषित कर रहा था। दूसरा यह आरोप लगाया गया था कि पहले प्रतिवादी के मुखर और धमकी भरे आचरण ने मतदाताओं को उसे वोट देने के लिए मजबूर और प्रभावित किया क्योंकि उन्हें अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। कई स्थानों पर आतंकवाद

का माहौल था जिसने मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से उनकी इच्छा और पसंद के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोक दिया । जनता दल पार्टी के एजेंट, जिनसे अपीलार्थी संबंधित थे, कुछ मतदान केंद्रों पर पूर्ण नियंत्रण में थे और वे हर चुनाव मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे। यह भी आरोप लगाया गया कि काफी अपीलार्थी के पक्ष में कई अमान्य मतों की गिनती की गई जैसे कि वे वैध थे। ऐसे आरोपों पर, प्रथम प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के चुनाव को अमान्य घोषित करने और खुद को विधिवत निर्वाचित घोषित करने के लिए प्रार्थना की, जबकि यह अभिनिर्धारित करते हुए कि पुनः गिनती का आदेश अमान्य था और इस तरह की पुनः गिनती का परिणाम गैर-अनुमानित था।

3. उपस्थिति दर्ज करने के बाद, अपीलार्थी ने कुछ अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने के लिए चुनाव याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज करने के लिए तीन आवेदन दायर किए। आई ए सं.IX, इस आधार पर था कि याचिका में कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं किया गया था क्योंकि अनुचित प्रभाव और पुनर्मतगणना के आरोपों के बाद कोई दावा नहीं किया गया था कि चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था; .न ही याचिका में पुनर्मतगणना के दौरान किसी त्रुटि या कदाचार के बारे में

कोई दावा किया गया था। आई.ए.सं.X चुनाव याचिका के साथ याचिकाकर्ता द्वारा दायर हलफनामे को अस्वीकार करने के लिए था क्योंकि यह कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था और इसके परिणामस्वरूप याचिका को खारिज कर दिया जाता। आई.ए.सं. XV याचिका को इस आधार पर खारिज करने के पक्ष में था कि भ्रष्ट आचरण के आरोप अस्पष्ट थे और तात्विक तथ्यों या विवरणों द्वारा समर्थित नहीं थे।

4. प्रथम प्रतिवादी और उत्तरदाता 7 और 8 द्वारा अन्य राहतों के लिए कुछ अन्य आवेदन दायर किए गए थे। उच्च न्यायालय ने उन सभी का निपटारा एक सामान्य आदेश दिनांक 21.3.96 द्वारा कर दिया । आवेदन आई. ए. सं.IX, X और X अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त रूप में दायर किए गए को खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने विशेष अनुमति प्राप्त की है और इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति प्राप्त की है और इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान चुनाव याचिका में सत्यापन और उसके समर्थन में याचिकाकर्ता द्वारा दायर हलफनामे की ओर

आकर्षित किया है और बताया है कि यह नियमों के नियम 94 ए या फॉर्म 25 के अनुरूप नहीं है। तर्क दिया कि पहले प्रतिवादी ने विशेष रूप से यह नहीं बताया था कि कौन से आरोप उसकी व्यक्तिगत जानकारी में थे और कौन से आरोप सूचना पर बताए गए थे । ऐसा करने में विफलता पूरी चुनाव याचिका को दूषित कर दिया और इसे खारिज करने योग्य बना दिया। दूसरे, उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता की निशानदेही पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पुनर्गणना नियम 63 द्वारा अपेक्षित नहीं थी और नियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी। उनके अनुसार, किसी भी स्थिति में, चुनाव याचिका में इस तरह की पुनर्मतगणना के दौरान किसी भी अवैधता या अनियमितता के कारित होने का कोई आरोप नहीं था; न ही ऐसा कोई आरोप था कि पुनर्मतगणना में ऐसी अवैधता या अनियमितता के कारण चुनाव के परिणाम पर कोई भौतिक प्रभाव पड़ा। तीसरा, उन्होंने तर्क दिया कि भ्रष्ट आचरण के आरोप बहुत अस्पष्ट थे और उनमें तात्विक तथ्य या विवरण शामिल नहीं थे। इस प्रकार, उनके अनुसार, इस अदालत द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित कानून के आलोक में चुनाव याचिका तत्काल खारिज किये जाने योग्य है।

6. इसके विपरीत, पहले प्रतिवादी के विद्वान वकील ने निम्नलिखित तर्क दिया हैः

चुनाव याचिका में उन मामलों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है जिनके बारे में याचिकाकर्ता को स्वयं जानकारी थी और जिन मामलों के बारे में उसने दूसरों से जानकारी प्राप्त की थी और उन पर विश्वास किया था। तथ्य यह है कि याचिका में हलफनामे या सत्यापन में मद की संख्या अलग से निर्धारित नहीं की गई थी, इससे याचिका की वैधता प्रभावित नहीं हुई। दूसरे, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा आदेश दिया गया पुनर्मतगणना नियम 63 के प्रावधानों का उल्लंघन था और उक्त अधिकारी अपीलकर्ता के पिता से अनुचित रूप से प्रभावित था। उनके अनुसार, पहला प्रतिवादी चार वोटों से आगे चल रहा था और अपीलकर्ता को चुनाव जिताने के लिए, पुनर्मतगणना के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को अपीलकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन की एक प्रति भी उपलब्ध कराए बिना पुनर्मतगणना का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश का पारित होना ही चुनाव को दूषित करने के लिए पर्याप्त था। तीसरा, यह तर्क दिया गया कि चुनाव याचिका में अपीलकर्ता और उसके पिता द्वारा भ्रष्ट आचरण का विस्तार से वर्णन किया गया है जैसा धारा 123(2), 123(7) (एफ) और 123(8) द्वारा परिभाषित है। यह आगे तर्क दिया गया

कि यह तथ्य कि अपीलार्थी ने दोषारोपण के लिए याचिकाएं दायर की थीं, यह दर्शाता है कि उसने आरोप स्वीकार कर लिया था चुनाव याचिका में निहित मुद्दे और उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ इस अदालत में अपील दायर करना उनके लिए खुला नहीं था।

7. हम पहले प्रत्यार्थी के अंतिम विवाद का तुरंत निपटारा कर सकते हैं चूंकि बिना किसी सार की है ।कार्यवाही की सीमा पर दायर दोषारोपण की याचिकाएँ केवल इस आधार पर थीं कि भले ही चुनाव याचिका में दिए गए दावों को सही माना जाए, याचिका खारिज की जा सकती है क्योंकि यह चुनाव कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि अपीलार्थी ने याचिका में लगाए गए आरोपों की सच्चाई को स्वीकार किया था।

8. चुनाव याचिका के अंत में सत्यापन इस प्रकार निम्नलिखित हैः

"मैं, श्री जी. पुट्टस्वामी गौड़ा, उपरोक्त याचिका में चुनाव याचिकाकर्ता, गंभीरता से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर पैरा 1 से 6 में जो कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और

तदनुसार मैंने उपरोक्त चुनाव पर हस्ताक्षर किए हैं जनवरी 1995 के इस 23 वें दिन बैंगलोर में याचिका"।

याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे में इस प्रकार कहा गया है:

"प्रतिवादी-1, निर्वाचित उम्मीदवार के भ्रष्ट आचरण करित करने के बारे में चुनाव याचिका के पैराग्राफ 1 से 6 में दिए गए बयान और ऐसे भ्रष्ट आचरण के विवरण, के पैराग्राफ 1 से 6 में उल्लेखित हैं। वही याचिका और उसके साथ संलग्न अनुलग्नक-ए से आर तक के पैराग्राफ मेरी जानकारी और सूचना के अनुसार सही हैं जैसा कि याचिका के मुख्य भाग में दिया गया है।"

9. न तो सत्यापन और न ही शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस न्यायालय ने शपथ पत्र का निर्धारित प्रपत्र में होने पर बार-बार महत्व और आवश्यकता पर जोर दिया है। अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत दो फैसलों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा।

10. डॉ. शिप्रा (श्रीमती) और अन्य बनाम शांतिलाल खोईवाल और अन्य, [1996] 5 एस. सी. सी. 181 में यह देखा गयाः

"नियम के नियम 94-ए के साथ पठित धारा 81,83 (1) (सी) और 86 और प्रपत्र 25 को एक अभिन्न योजना के रूप में संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा पढ़ने पर, यदि अदालत को चुनाव याचिका की स्थिरता के बारे में निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा उठाई गई आपत्ति पर पता चलता है, तो अदालत को प्रश्न पर विचार करना होगा और प्रारंभिक आपत्ति पर निर्णय लेना होगा। यदि अदालत इसे बरकरार नहीं रखती है, तो मुकदमा चलाने की आवश्यकता उत्पन्न होगी। यदि अदालत प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रखती है, तो चुनाव याचिका को जल्द ही खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि अदालत के पास इसे खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।"

11. हाल ही में एल. आर. शिवरामगौड़ा, आदि बनाम टी. एम. चंद्रशेखर आदि, (1998) 6 एससीएएलई 361, इस मामले को कुछ हद तक यहाँ निपटाया गया था। अदालत ने विरेंद्र कुमार सक्लेचा बनाम जगजीवन और अन्य , [1972] ' 1 एस. सी. सी. 826 का उल्लेख किया और एक अंश का हवाला दिया जिसमें हलफनामे में सूचना के स्रोतों का खुलासा करने के महत्व पर जोर दिया गया था। इसके बाद में इसी तरह के विचार रखने वाले फैसलों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहाः

"16. यदि उपरोक्त सुस्थापित सिद्धांतों को इस मामले में लागू किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन याचिका कथित भ्रष्ट आचरण के तात्विक तथ्यों को स्थापित करने में विफलता के एक बहुत ही गंभीर दोष से ग्रस्त है। यह दोष चुनाव याचिका को अमान्य कर देता है। उस संबंध में और याचिकाकर्ता को उसके संदर्भ में कोई सबूत पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।

16ए. हम पहले ही मद (एफ) और (जी) निकाल चुके हैं चुनाव याचिका के साथ दाखिल किया गया शपथ पत्र के। यह सूचना के स्त्रोत का खुलासा नहीं करता है। न ही यह निर्धारित किया गया है कि चुनाव याचिका का कौन सा हिस्सा याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से पता था और कौन सा हिस्सा उसे सूचना पर पता चला। महत्त्वपूर्ण रूप से, हलफनामे के पैराग्राफ (ए) से (ई) में कहा गया है कि उसमें दिए गए कथन उसकी जानकारी के अनुसार सही हैं। पैराग्राफ (एफ) मामले के इस पहलू पर चुप है। अनुच्छेद (जी) याचिका के सभी 42 अनुच्छेदों को संदर्भित करता है। हलफनामा निर्धारित प्रपत्र संख्या 25 के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार चुनाव संचालन नियमों के नियम 94-ए का अनुपालन करने में विफलता है। यह एक बहुत ही गंभीर दोष है जिसे उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया है।"

12. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय में उपयोग लिए जाने वाले हलफनामों से संबंधित कर्नाटक उच्च न्यायालय नियम, 1959 के के प्रावधानों पर निर्भर किया. O.XI. नियम 4 इस प्रकार हैः

"जब एक शपथ पत्र में तथ्यों के बयान होते हैं जो घोषणाकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी के भीतर नहीं होते हैं, बल्कि सूचना पर आधारित होते हैं घोषणाकर्ता द्वारा प्राप्त, वह ऐसा बताएगा और वह उन्हें सच मानता है और ऐसी सूचना का स्रोत भी देगा जहाँ भी संभव हो और उसके विश्वास का आधार यदि कोई हो।"

13. इसलिए अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि चुनाव याचिका को तत्काल रूप से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

14. इसमें कोई संदेह नहीं है कि तर्क आकर्षक है। लेकिन, अधिनियम में प्रासंगिक प्रावधान बहुत विशिष्ट हैं। धारा 86 में धारा 81,82 और 117 का अनुपालन न करने के लिए तत्काल रूप से चुनाव याचिका को रद्द करने का प्रावधान है। धारा 81 यह चुनाव याचिका प्रस्तुत करने से संबंधित है। यह हमारे समक्ष अपीलार्थी का मामला नहीं है कि धारा 81 की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था, यद्यपि उच्च न्यायालय में यह तर्क दिया

गया था कि चुनाव याचिका की सही प्रति अपीलकर्ता को नहीं दी गई थी और इस प्रकार धारा 81 के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया। इस मामले में धारा 82 और 117 प्रासंगिक नहीं हैं। ध्यान देने योग्य है कि धारा 86 धारा 83 का उल्लेख नहीं करती है और धारा 83 का अनुपालन न करने पर धारा 86 के तहत बर्खास्तगी नहीं होती है। इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि धारा 83 की अनुपालन न करने पर याचिका खारिज हो सकती है यदि मामला इसके अंतर्गत आता है ओ.6, आर. 16 या ओ.7., आर, 11 सी.पी.सी. । चुनाव याचिका या चुनाव याचिका के साथ हलफनामे के सत्यापन में दोष को उपाय योग्य माना गया है, घातक नहीं।

15. मुरारका राधे श्याम राम कुमार बनाम रूप सिंह राठौड़ और अन्य, [1964] 3 एस.सी.आर. 573, में एक संविधान पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अधिनियम की धारा 83(1)(सी) के अनुसार आवश्यक चुनाव याचिका के सत्यापन में कोई दोष याचिका की स्थिरता के लिए घातक नहीं था और सत्यापन में दोष याचिका खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था। चौ.सुब्बाराव बनाम सदस्य, चुनाव न्यायाधिकरण, हैदराबाद, [1964] 6 एस.सी.आर. 213, कि धारा 81(3) में भी एक और संविधान पीठ ने कहा कि धारा 81(3) के संबंध में भी, आवश्यकता का सारवान अनुपालन पर्याप्त

था और केवल पूर्ण या सम्पूर्ण रूप से धारा 81(3) के प्रावधानों का अनुपालन न होने के मामलों में, यह कहा जा सकता है कि चुनाव याचिका अधिनियम के उस भाग के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं की गई थी।

16. यह पर्याप्त अनुपालन का उक्त सिद्धांत है जो के. एम. मणि बनाम. जे. एंटनी और अन्य, [1979] 2 एस. सी. सी. 221 में अपनाया गया। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा उस पर सही रूप से निर्भरता रखी गई।

17. एफ. ए. सापा और अन्य बनाम सिंगोरा और अन्य, [1991] 3 एस. सी. सी. 375, में अदालत ने माना कि याचिका के सत्यापन में दोष के साथ-साथ शपथपत्र में दोष का भी उपाय किया जा सकता है और यह याचिका की स्थिरता के लिए घातक नहीं है। न ही विरेंद्र कुमार सक्लेचा बनाम में जगजीवन और अन्य, [1972] 1 एस. सी. सी. 826, न ही एल. आर. शिवरामगौड़ा, आदि बनाम टी. एम. चंद्रशेखर आदि, [1998] 6 एससीएएलई 361 में इस न्यायालय ने इस हद तक निर्णय दिया कि शपथ पत्र या सत्यापन में कमी के लिए चुनाव याचिका को तत्काल रूप से खारिज कर दिया जाना चाहिए। वास्तव में प्रश्न को स्पष्ट रूप से खुला छोड़ दिया गया था पूर्व मामले में और यह बाद वाले में उत्पन्न नहीं हुआ।

18. डॉ. शिप्रा (श्रीमती) और अन्य बनाम शांतिलाल खोईवाल और अन्य, [1996] 5 एस. सी. सी. 181 में निर्णय उसमें पाए गए तथ्यों पर आधारित था। उस मामले में विद्वान न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणियों को व्यापक पाया गया और मामले को एक तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एक बड़ी पीठ को भेजा गया है टी. एम. जैकब बनाम ओ. पौलोस और अन्य , [1998] 2 एस. सी. सी 31 । किसी भी स्थिति में, डॉ. शिप्रा के मामले में निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि तथ्य अलग हैं।

19. अपीलार्थी, के लिए विद्वान वकील के दूसरे तर्क के संबंध में यह प्रश्न कि क्या निर्वाचन अधिकारी द्वारा मामले की परिस्थितियों में पुनः गणना का आदेश देना उचित था और क्या इस तरह की पुनः गणना नियम 63 के दायरे में आती है, मुकदमे में तय किया जाना है। इस स्तर पर उस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त नहीं की जा सकती है जब तक कि पक्षकार उस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत न करें।

20. इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि चुनाव याचिका इस तरह की पुनः गणना के दौरान, की गई अवैधताएं उजागर नहीं करती । बहुत से आक्षेप याचिका में इस आशय के हैं कि पुनः मतगणना का आदेश अपने आप में अवैद्य था जो चुनाव के परिणाम को दूषित करने वाली एक अवैधता

थी और यह भी इस तरह की पुनर्गणना के दौरान, कई अवैधताएं की गईं जिससे चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित रहा। इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि याचिका में कहा गया कि बड़ी संख्या में मतपत्र जो अमान्य थे और अस्वीकार किए जाने योग्य थे, अपीलार्थी के पक्ष में वैध मतों के रूप में गिने गए। अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का प्रयास चुनाव याचिका को दो अलग-अलग खंडों में विभाजित विभाजित करना है , जिनमें से एक पुनः गणना से संबंधित है और दूसरा भ्रष्ट आचरण से संबंधित है। चुनाव याचिका को इस तरह से विच्छेदित करना संभव नहीं है। अमान्य मतों के बारे में आरोप निस्संदेह मद 3 में जगह पाते हैं लेकिन उन्हें पुनर्गणना से संबंधित कथनों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

21. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान चंदा सिंह बनाम चौधरी शिवराम वर्मा और अन्य, [1975] 4 एस. सी. सी. 393 की ओर आकर्षित किया । उस मामले में यह माना गया था कि बहुत कम मतों से जीत निश्चित रूप से अन्य परिस्थितियों को देखते हुए गिनती में अनजाने में त्रुटि होने का डर हो सकता है। लेकिन न्यायालय ने निर्वाचन अधिकारी को फिर से गिनती की प्रक्रिया चलाने के लिए याचिका की वैधता का आंकलन करने में बहुत सावधान, उद्देश्यपूर्ण और संवेदनशील होने की

चेतावनी दी थी। विद्वान् वकील द्वारा निर्दिष्ट अन्य निर्णय, मामले के इस पहलू पर एस. बलदेव सिंह बनाम हैं। तेजा सिंह स्वतंत्र (मृत) और अन्य, [1975] 4 एस. सी. सी. 406 का है । वही बेंच जिसने चंदा सिंह के मामले पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियम 63 का आदेश यह है कि फिर से गिनती की अनुमति अपवाद नहीं है और इनकार उन मामलों तक ही सीमित था जहां मांग स्वयं तुच्छ या अनुचित थी और प्रत्येक मामले की परिस्थितियां मामले का फैसला करती हैं। पीठ ने यह भी कहा कि जहां अंतर का फ़र्क न्यूनतम था, वहां नई गिनती के दावे को व्यर्थ या भारी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। । ये दोनों फैसले इस स्तर पर अपीलकर्ता की मदद नहीं करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, मामला उन तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिन्हें मुकदमे में साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना है।

22. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का तीसरा तर्क भ्रष्ट आचरण के आरोपों से संबंधित है। हम उनके तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि वे अस्पष्ट हैं और उनमें तात्विक तथ्य नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका के प्रासंगिक भागों को निकाला है जो भ्रष्ट आचरण से संबंधित हैं।

पूरी याचिका पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

"इसलिए, इन और चुनाव याचिका के अन्य मदों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर पहले प्रत्यार्थी द्वारा करित या किए गए भ्रष्ट आचरण के बारे में बताया है। चुनाव याचिका में लिए गए आधारों के अवलोकन के बाद, मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क में बल नजर आता है कि इसमें चुनाव और प्रत्यार्थी -1 द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण को अमान्य करने के लिए कार्रवाई के कारण बनने वाले आवश्यक तथ्य शामिल हैं, आरोपों का सारवान रूप से अनुरोध किया गया है। चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन, यह मानना संभव नहीं है कि चुनाव याचिका किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा नहीं करती है या किसी भी भ्रष्ट आचरण का भौतिक विवरण नहीं देती है। यह कहा जाना आवश्यक है कि भले ही अदालत इस बात से संतुष्ट हो कि भ्रष्ट आचरणों में से किसी एक के संबंध में कथित तात्विक तथ्य और उसके पूर्ण विवरण नहीं बताए गए हैं, फिर भी चुनाव याचिका को तत्काल ही नहीं खारिज किया जा सकता है, यदि अन्य भ्रष्ट आचरण के संबंध में भौतिक तथ्य और पूर्ण विवरण अधिनियम की धारा

83(1) की आवश्यकता के अनुसार दिए गए हैं। जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने सही तर्क दिया है, चुनाव याचिका की सामग्री को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और उन्हें संदर्भ से अलग नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें काट-छाँट कर नहीं पढ़ा जा सकता। यदि इस परीक्षण को चुनाव याचिका के मद 2 और 3 में दिए गए कथनों पर लागू किया जाता है, तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि समग्र रूप से लिए गए ये मद धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण के कारितकरने के संबंध में आरोपों से संबंधित हैं। अधिनियम और अन्य अनियमितताओं के संबंध में भी जो प्रत्यार्थी -1 के चुनाव को अमान्य करता है ।

उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए उपरोक्त दृष्टिकोण से हम पूरी तरह सहमत हैं।

23. इस न्यायालय ने बार-बार तात्विक तथ्यों' और 'विशेषताओं' के बीच अंतर बताया है। जहां तक तात्विक तथ्यों' का सवाल है, इस न्यायालय ने माना है कि उन्हें चुनाव याचिका में पूरी तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यदि कोई तथ्य सामने नहीं रखा गया है, तो याचिकाकर्ता को बाद में उससे संबंधित साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है; न ही उसे चुनाव याचिका के लिए निर्धारित सीमा अवधि की समाप्ति के बाद

याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी। जहां तक विवरण का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा व्यक्त सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि विवरण के अभाव में याचिका को तत्काल खारिज नहीं किया जा सकता है और यदि न्यायालय को लगता है कि विवरण आवश्यक है, तो याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने का अवसर दिया जाना चाहिए और विवरण शामिल करें । श्री बलवान सिंह बनाम श्री लक्ष्मी नारायण एवं अन्य में संविधान पीठ, [1960] 3 एस.सी.आर. 91 में माना गया कि एक चुनाव याचिका केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि कथित भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण निर्धारित नहीं किया गया था। यह देखा गया कि यदि कोई आपत्ति ली गई थी और ट्रिब्यूनल का मानना था कि विवरण निर्धारित नहीं किया गया है, याचिकाकर्ता को विवरणों को संशोधित करने या बढ़ाने का अवसर दिया जाना चाहिए और केवल विवरण प्रदान करने के आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में ही आरोप को हटाया जा सकता है।

24. राज नारायण बनाम श्रीमती इंदिरा नेहरू गाँधी और अन्य , [1972] 3 एस. सी. सी. 850 में प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की गई और यह

अभिनिर्धारित किया गया कि अभिवचनों को सख्ती से समझने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित परिच्छेद को निकालना लाभप्रद है:

"जब एक भ्रष्ट आचरण को सख्ती से साबित किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव कार्यवाही में एक दलील को सख्त आधार मिलना चाहिए। इस न्यायालय ने माना है कि एक दोषपूर्ण आरोप भी एक आपराधिक मुकदमे को तब तक दूषित नहीं करता जब तक कि यह साबित न हो जाए कि इसने अभियुक्त को पूर्वाग्रहित कर दिया है। यदि उचित व्याख्या पर दलील कार्रवाई को कायम रख सकती है, तो अदालत को उस व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए। अदालतें तकनीकी आधार पर किसी कार्रवाई को विफल करने के लिए अनिच्छुक हैं। भ्रष्ट आचरण का आरोप एक बहुत ही गंभीर आरोप है । चुनाव की शुचिता वास्तविक लोकतंत्र का सार है। प्रश्न में लगाए गए आरोप को प्रतिवादी ने अस्वीकार कर दिया है। इसे अभी तक साबित नहीं किया गया है। यह साबित हो भी सकता है और नहीं भी। अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप अंततः साबित हो सकते हैं पूरी तरह से सत्य से रहित साबित हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ता को अपने आरोप साबित करने का अवसर देने से इनकार कर दिया जाना चाहिए? क्या अदालत को उन आरोपों की जांच करने से केवल

इसलिए इनकार कर देना चाहिए क्योंकि अपीलकर्ता या उसका संक्षिप्त विवरण तैयार करने वाला कोई व्यक्ति कानून की भाषा नहीं जानता था। हमें उन प्रश्नों का नकारात्मक उत्तर देने में कोई झिझक नहीं है। कानून के शासन के निहितार्थ बहुआयामीहैं।" (पैरा 16)

X X X

19. अभिवचन के नियमों का उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई और उचित निर्णय तक पहुंचने में सहायता करना है। कानून की कार्रवाई को शतरंज के खेल के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। कानून के प्रावधान केवल अनुष्ठान के रूप में पालन किए जाने वाले सूत्र नहीं हैं। कानून के प्रावधान के शब्दों में, नीचे, आम तौर पर कहें तो, वहां एक न्यायिक सिद्धांत निहित है। उस सिद्धांत को सुनिश्चित करना और उसे लागू करना अदालत का कर्तव्य है।"

25. उपरोक्त नियमों को वर्तमान मामले में लागू करते हुए उच्च न्यायालय ने अपील के तहत फैसले में निम्नानुसार उचित टिप्पणी की है:

"इसलिए, मेरे विचार में, चुनाव याचिका के मद 2 और 3 में दिए गए कथन समग्र रूप से पढ़े जाएंगे और पूरी तरह से अधिनियम की धारा 83(1) की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से संतुष्ट करेंगे, जहां तक कि तात्विक

तथ्य भी हैं, जिन पर चुनाव को अमान्य करने वाले भ्रष्ट आचरण और अन्य अवैधताओं का आरोप लगाने के लिए, प्रतिवादी नंबर 1 को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए निर्भर किया गया था। वास्तव में, चुनाव याचिका में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के दायरे और परिधि को स्पष्ट रूप से समझने के बाद, प्रतिवादी नंबर 11 अदालत में प्रस्तुत किए गए आरोप-प्रत्यारोप के नोटिस दायर के साथ एक दोषारोपण याचिका दायर करने में सक्षम हो गया है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण और चुनाव को अमान्य करने वाली अन्य अवैधताओं की वकालत करने में कोई कमी नहीं है।"

26. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान धरमवीर आदि आदि बनाम अमर सिंह और अन्य आदि आदि, [1996] 3 एस. सी. सी. 158 की ओर आकर्षित किया है। दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 123 की उप-धारा (2) और (7) केवल वोट डालने से पहले के स्तर पर किए गए भ्रष्टाचार के मामलों पर लागू होती हैं, न कि मतदान के बाद के स्तर पर। मामले में तथ्य पूरी तरह से अलग थे। यह भी बताया गया है निर्णय में कि उस मामले में चुनाव और गिनती अधिनियम की धारा 128 (8) और 135 ए (डी) और उन प्रावधानों को

शामिल करने से पहले समाप्त हो गई थी और वो प्रावधान संचालन में पूर्वव्यापी नहीं थे और इसलिए मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते थे। वर्तमान मामले में चुनाव उक्त प्रावधानों को शामिल करने के लंबे समय बाद 1994 में आयोजित किया गया था और इसलिए इस मामले में निर्णय लागू नहीं होता है।

27. प्रारंभिक आपत्ति के सभी मामलों में परीक्षण में यह देखना है कि यदि याचिका में दिए गए कथन सही साबित होते हैं तो याचिकाकर्ता को याचिका की गई कोई राहत दी जा सकती है या नहीं। यदि प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो याचिका की स्थिरता को बरकरार रखना होगा। वर्तमान मामले में हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि चुनाव याचिका में शामिल आरोप याचिकाकर्ता द्वारा सही साबित होते हैं, तो वह याचिका भाग में निर्धारित राहत पाने का हकदार होगा। इसलिए, हमें अपीलों में कोई योग्यता नहीं मिली और उन्हें जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है। वकील की फीस रु. 5,000. (एक सेट)

अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता चित्रा भदौरिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।